भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 231
मंगलवार, 21 जुलाई, 2026/30 आषाढ़, 1948 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी आंदोलन का सुदृढ़ीकरण

†231. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 और श्वेत क्रांति 2.0 के कार्यान्वयन से डिजिटल शासन को बढ़ावा देकर, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का विस्तार, डेयरी सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण और देश भर में किसानों की आय में वृद्धि करके सहकारी आंदोलन को मजबूती मिली है;
(ख) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर कंप्यूटरीकृत और ऑनबोर्ड की गई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, स्थापित की गई नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और डेयरी सहकारी समितियों का ओडिशा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) कंधमाल, बौद्ध, नयागढ़ और गंजाम जिलों सहित जिला-वार प्रदान की गई सहकारी संस्थाओं, डेयरी अवसंरचना, दुग्ध संग्रहण सुविधाओं और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या पारदर्शी और कुशल शासन के लिए इन पहलों के कार्यान्वयन और निगरानी के साथ राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को जोड़ा गया है; और
(ङ) क्या सरकार का आकांक्षी जिलों और जनजातीय क्षेत्रों, विशेष रूप से कंधमाल में सहकारी और डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) जी हां, मान्यवर । राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 जिसमें श्वेत क्रांति 2.0 शामिल है, का लक्ष्य सहकारी क्षेत्र का डिजिटलीकरण, सभी अनाच्छादित पंचायतों को आच्छादित करने के लिए प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स), प्राथमिक डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों के विस्तार को बढ़ावा देना, बहुउद्देशीय पैक्स को प्रोत्साहन, आदि द्वारा सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और समग्र विकास के माध्यम से देश भर में सहकारी आंदोलन को सशक्त करना है । इसके अलावा, इस नीति में *'सहकार-से-समृद्धि'* की परिकल्पना की प्राप्ति हेतु सहकारी कार्यकलापों के विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, बेहतर बाजार पहुंच, निर्यात को बढ़ावा, क्षमता निर्माण और सहकारी व्यवसाय परितंत्र के सशक्तीकरण द्वारा सदस्यों और किसानों की आय बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

इसके अतिरिक्त, श्वेत क्रांति 2.0 के कार्यान्वयन ने डेयरी सहकारी समितियों को सशक्त किया है और सहकारी क्षेत्र में दुग्ध प्रापण में वृद्धि की है । श्वेत क्रांति 2.0 के शुभारंभ के बाद से 24,097 नए डीसीएस स्थापित

किए गए हैं और 31,394 मौजूदा डीसीएस को सशक्त किया गया है तथा सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2023-24 में दुग्ध प्रापण 660 एलकेजी प्रतिदिन से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 697 एलकेजी प्रतिदिन हो गई है ।

(ख) और (ग): सरकार ने वर्ष 2022 में पैक्स कंप्यूटरीकरण की केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना शुरू की है । भारत सरकार ने कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना के अधीन प्रारंभ में 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय से 63,000 पैक्स को अनुमोदित किया था, जिसे अब 79,630 पैक्स को शामिल करते हुए बढ़ाकर 2925.39 करोड़ रुपये किया गया है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है । तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा **संलग्नक-1** पर दिया गया है ।

इसके अलावा, सरकार द्वारा की गई पहलों के परिणामस्वरूप, दिनांक 15.02.2023 से देश भर में 38,138 नए पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं । नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की पहल को नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी द्वारा डेयरी अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) और पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) सहित भारत सरकार की मौजूदा विभिन्न योजनाओं के अभिसरण द्वारा समर्थित किया गया है । स्थापित की गई पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों के साथ-साथ उनके साथ जुड़े सदस्यों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-2 के रूप में रखा गया है। ओडिशा में 8,667 सहकारी समितियां हैं, जिनमें से 8,063 काम कर रही हैं। राष्ट्रीय योजना के तहत, राज्य में 2,609 नई सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं, जिनमें 1,539 बहुउद्देशीय पीएसीएस/एलएएमपीएस (लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज), 1,009 डेयरी सहकारी समितियाँ और 61 मात्स्यिकी सहकारी समितियाँ शामिल हैं । इसके अलावा 466 मौजूदा डेयरी समितियों को सशक्त किया गया है ।

ओडिशा के चार जिलों - कंधमाल, बौध, नयागढ़ और गंजम में सहकारी संस्थानों का ब्योरा निम्नानुसार है:

I. सहकारी समितियों की कुल संख्या:

जिला	कुल सहकारी समितियां	पैक्स/एलएएमपीएस/ एफएसएस	डेयरी सहकारी समितियां	मात्स्यिकी सहकारी समितियां
कंधमाल	105	76	0	2
बौध	105	46	21	1
नयागढ़	255	187	0	7
गंजम	625	422	24	93

II. मंत्रालय की पहलों के माध्यम से स्थापित नई सहकारी समितियों की संख्या:

जिला	पैक्स/एलएएमपीएस/ एफएसएस	डेयरी सहकारी समितियां	मात्स्यिकी सहकारी समितियां	कुल
कंधमाल	52	0	0	52
बौध	4	21	0	25
नयागढ़	28	0	2	30
गंजम	23	12	6	41

(घ) एनसीडी न केवल किसी नीतिगत पहल के प्रतिपादन के दौरान बल्कि नीति कार्यान्वयन के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । यह डेटाबेस सहकारी समितियों के भौगोलिक आच्छादन, वित्तीय प्रदर्शन, आदि में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और इस प्रकार नीति सिफारिशों को कार्यान्वित करने में मदद करता है । यह डेटाबेस अनाच्छादित और अल्प-आच्छादित क्षेत्रों में नई पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है, रैंकिंग संरचना के विकास को सक्षम बनाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र के आर्थिक योगदान का अनुमान लगाने में सहायता प्रदान करता है ।

(ङ) मंत्रालय की पहल के माध्यम से देश भर के आकांक्षी जिलों में 1850 नए पैक्स, 3638 नई डेयरी सहकारी समितियां और 448 नई मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं । विशेष रूप से ओडिशा के कंधमाल जिले में 2,38,277 की कुल सदस्यता वाली 105 सहकारी समितियां हैं, जिनमें 76 एलएएमपीएस/पैक्स और 2 मात्स्यिकी सहकारी समितियां शामिल हैं । 72 एलएएमपीएस/पैक्स में से 52 एलएपीएमएस/पैक्स मंत्रालय की पहल के माध्यम से स्थापित किए गए हैं ।

इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) जो सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निगम है, को सहकारी संस्थानों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिदेशित किया गया है । दिनांक 30.06.2026 तक, एनसीडीसी ने देश भर में सहकारी संस्थानों के विकास के लिए संचयी रूप से 5,74,090.48 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं । इसमें से 3,352.03 करोड़ रुपये ओडिशा राज्य में सहकारी विकास के लिए संवितरित किए गए हैं । राज्य में विगत पांच वर्षों के दौरान किए गए संवितरण का ब्योरा **संलग्नक-3** में दिया गया है । तथापि, पिछले पांच वर्षों के दौरान एनसीडीसी को ओडिशा राज्य के कंधमाल जिले से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

*****

संलग्नक-1

क्रम सं.	राज्य	पंजीकृत एम-पैक्स	पंजीकृत डीसीएस
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	2
2	आंध्र प्रदेश	11	1,067
3	अरुणाचल प्रदेश	136	25
4	असम	580	725
5	बिहार	61	4,498
6	छत्तीसगढ़	517	361
7	गोवा	38	5
8	गुजरात	662	810
9	हरियाणा	40	197
10	हिमाचल प्रदेश	136	854
11	जम्मू और कश्मीर	232	1,339
12	झारखंड	45	300
13	कर्नाटक	265	1,264
14	केरल	0	0
15	लद्दाख	3	3
16	लक्षद्वीप	0	0
17	मध्य प्रदेश	680	1,349
18	महाराष्ट्र	212	1,223
19	मणिपुर	127	27
20	मेघालय	290	17
21	मिजोरम	97	2
22	नागालैंड	50	5
23	ओडिशा	1539	1,009
24	पुदुचेरी	4	3
25	पंजाब	153	1,027
26	राजस्थान	2003	3,295
27	सिक्किम	27	77
28	तमिलनाडु	27	940
29	तेलंगाना	0	166
30	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	5	0
31	त्रिपुरा	294	2
32	उत्तर प्रदेश	1364	4,450
33	उत्तराखंड	606	269
34	पश्चिम बंगाल	25	241
कुल		**10230**	**25,552**

संलग्नक-2

क्रम सं.	राज्य	पैक्स	डीसीएस	एफसीएस	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	2	11	14
2	आंध्र प्रदेश	11	1,067	2	1,080
3	अरुणाचल प्रदेश	136	25	29	190
4	असम	580	725	89	1,394
5	बिहार	61	4,498	2	4,561
6	छत्तीसगढ़	517	361	336	1,214
7	गोवा	38	5	4	47
8	गुजरात	662	810	26	1,498
9	हरियाणा	40	197	6	243
10	हिमाचल प्रदेश	136	854	12	1,002
11	जम्मू और कश्मीर	232	1,339	40	1,611
12	झारखंड	45	300	227	572
13	कर्नाटक	265	1,264	52	1,581
14	केरल	0	0	0	0
15	लद्दाख	3	3	1	7
16	लक्षद्वीप	0	0	29	29
17	मध्य प्रदेश	680	1,349	255	2,284
18	महाराष्ट्र	212	1,223	167	1,602
19	मणिपुर	127	27	71	225
20	मेघालय	290	17	19	326
21	मिजोरम	97	2	2	101
22	नागालैंड	50	5	19	74
23	ओडिशा	1,539	1,009	61	2,609
24	पुदुचेरी	4	3	3	10
25	पंजाब	153	1,027	52	1,232
26	राजस्थान	2,003	3,295	31	5,329
27	सिक्किम	27	77	4	108
28	तमिलनाडु	27	940	36	1,003
29	तेलंगाना	0	166	102	268
30	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	5	0	1	6
31	त्रिपुरा	294	2	26	322
32	उत्तर प्रदेश	1,364	4,450	514	6,328
33	उत्तराखंड	606	269	124	999
34	पश्चिम बंगाल	25	241	3	269
कुल		**10,230**	**25,552**	**2,356**	**38,138**

संलग्नक -3

ओडिशा में विगत 5 वर्षों में कार्यकलाप-वार संवितरण

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	कार्यकलाप	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 दिनांक 30.06.2026 के अनुसार
1	विपणन	0.63			0.40	-	1.10
2	सेवा सहकारी समिति	3.02			0.20	0.15	
3	डेयरी और पशुधन			0.30	0.39	0.12	
4	एफपीओ	0.27	1.14	2.04	1.95	2.22	0.43
5	मात्स्यिकी	0.15	0.07	0.04			
6	मत्स्य किसान एफपीओ (एफएफपीओ)		0.40	0.87	2.47	3.55	
7	कंप्यूटरीकरण					0.61	
8	भंडारण				0.48	0.38	
	कुल	**4.07**	**1.61**	**3.25**	**5.89**	**7.03**	**1.53**